(2007) 13 SCR 165

सेवा राम और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

11 दिसम्बर 2007

[डॉ अरिजीत पसायत और आफताब आलम, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 सहपठित धारा 34 - के तहत दोषसिद्धि- आरोपियों ने रंजिश के चलते मृतक की लाठी व कंठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी-निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि-की शुद्धता- निर्णय: मामले के तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, निचली अदालतों द्वारा अभियुक्तों की सजा को बरकरार रखा गया।

धारा 34-प्रयोज्यता-प्रकृति और कार्यक्षेत्र-चर्चा की गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पक्षों के बीच मुकदमेबाजी की दुश्मनी के कारण आरोपियों ने 'GD' की हत्या कर दी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, तीन आरोपियों ने लाठियों से और एक आरोपी ने कंठी से 'GD' को पीटा। शिकायतकर्ता और 'JN' जो 'GD' के साथ थे, मदद के लिए चिल्लाए। आरोपी 'RP' और 'SR' ने शिकायतकर्ता को लाठियों से पीटा। 'GD' ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। एफआईआर दर्ज कराई गई. जांचें की गईं.

आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 34 और धारा 323 के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए। ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता और 'JN' की गवाही पर भरोसा करते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अपीलकर्ता 'SR' और 'RP' को आईपीसी की धारा 34 सहपठित धारा 323 के तहत भी दोषी ठहराया गया। हालाँकि, लंबित रहने के दौरान आरोपी 'RP' की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार उसकी अपील समाप्त हो गई। हाई कोर्ट ने आदेश बरकरार रखा. इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता-अभियुक्त व्यक्तियों ने तर्क दिया कि भले ही अभियोजन संस्करण को समग्र रूप से स्वीकार कर लिया जाए, धारा 302 के तहत अपराध नहीं बनता है, धारा 34 आईपीसी के आवेदन से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। यह धारा केवल साक्ष्य का नियम है और कोई ठोस अपराध नहीं बनाती। अनुभाग की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कृत्य अपराध

करने में शामिल होने वाले व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। सामान्य इरादे का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, ऐसे इरादे का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और सिद्ध परिस्थितियों से सामने आने वाली परिस्थितियों से ही लगाया जा सकता है। सामान्य इरादे के आरोप को सामने लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को साक्ष्य, चाहे प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य, द्वारा यह स्थापित करना होगा कि जिस अपराध के लिए उन पर आरोप लगाया गया है, उसे करने के लिए सभी आरोपी व्यक्तियों के दिमाग में योजना या सहमति थी। धारा 34, चाहे वह पूर्व-व्यवस्थित हो या तात्कालिक हो; लेकिन यह आवश्यक रूप से अपराध के घटित होने से पहले होना चाहिए। धारा की वास्तविक अवधारणा यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानून में स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो। [170-**G-H**-;171-**A-C**]

1.2. यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने का आरोप लगाए गए कई व्यक्तियों के कार्य समान या समान रूप से समान हों। कार्य चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन प्रावधान को आकर्षित करने के लिए उन्हें एक ही सामान्य इरादे से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। (**Para** 12) [171-**D**]

1.3 धारा 'सभी के सामान्य इरादे' नहीं कहती है, न ही यह "सभी के लिए एक आम इरादा' कहती है। धारा 34 के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार आरोपी को प्रेरित करने वाले एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना है। ऐसे इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य करना। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप, जब किसी आरोपी को धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानून में इसका मतलब है कि आरोपी उस कार्य के लिए उत्तरदायी है जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई, जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था। प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामले को पूरा करना है जिसमें किसी पार्टी के व्यक्तिगत सदस्यों के कृत्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है जो सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं या यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि उनमें से प्रत्येक ने क्या भूमिका निभाई थी। (**Para** 13) [171-**E-F**]

1.4 धारा 34 तब भी लागू होती है, जब विशेष अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट न पहुंचाई गई हो। धारा 34 लगाने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष कृत्य दिखाना आवश्यक नहीं है। (**Para** 13) [171-**G**]

2. उच्च न्यायालय ने सही माना कि चश्मदीद गवाह शिकायतकर्ता-**PW** 1 और **JN-PW** 3 के साक्ष्य में कोई खराबी नहीं थी। जब तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ऊपर प्रकाश डाले गए सिद्धांतों के आलोक में विचार किया

जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 34 के साथ पढ़ी गई धारा 302 के संदर्भ में सही रूप से दोषी ठहराया गया था। (Paras 10 and 15) [170-E; 172-A-B]

अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य **1977 (1) SCC 746**; चिंता पुल्ला रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य **1993 सप्लिमेंट (3) SCC 134**; गिरिजा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **2004(3) SCC 793 - पर आधारित**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2007 की आपराधिक अपील संख्या 1695

आपराधिक अपील संख्या 1845/1981 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27.5.2005 के अंतिम निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से बलराज दीवान।

प्रतिवादी की ओर से सहदेव सिंह, संदीप सिंह और अणुव्रत शर्मा

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अपील सुनवाई हेतु स्वीकार्य।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज करने के फैसले को दी गई है। हाईकोर्ट के समक्ष तीन लोगों ने अपील दायर की थी। अपील के लंबित

रहने के दौरान अपीलकर्ता क्रमांक 2 राम प्रसाद की मृत्यु हो गई। इसलिए, जहां तक उनका संबंध है, अपील को उकसाने वाला माना गया।

3. अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने का दोषी पाया गया और प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता-सेवा राम और मृतक-अभियुक्त राम प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 सहपठित धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को छह महीने के लिए आरआई से गुजरने और डिफ़ॉल्ट रूप से 500/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

4. यह दोषसिद्धि 1980 के सत्र परीक्षण संख्या 249 में IV अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत द्वारा दर्ज की गई थी।

5. मुकदमे के दौरान सामने आया अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार है:

शिकायतकर्ता शौकत अली, पुत्र नत्थू बक्स, निवासी बड़हरा, थाना. बीसलपुर, श्रीमती के रिश्तेदार गांव चांदपुरा निवासी जगन नाथ के घर पर सेवा करता था। गेंदा देवी, ज्वाला प्रसाद कुर्मी की विधवा, निवासी नौगामिया, थाना. बिलसंडा, जिसे आगे चलकर 'मृतक' कहा जाएगा। श्रीमती के बीच मुकदमा चल रहा था। गेंदा देवी और उनकी सौतेली बेटी

श्रीमती। जो नौगमिया गांव के राम प्रसाद की पत्नी के रूप में रहती थी। दिनांक 22.8.1980 को शिकायतकर्ता शौकत अली, जगन नाथ और श्रीमती गेंदा देवी के साथ मुकदमे के सिलसिले में तहसील बीसलपुर गए थे और वे लगभग 4' 0 बजे तहसील से ग्राम चंदपुरा लौट रहे थे और जब वे गाँव के बाहरी इलाके में पहुँचे सुबह 6 बजे कनगवां बाबूजी के गन्ने के खेत के पास श्रीमती गेंदा देवी आगे जा रही थीं; उसके पीछे शिकायतकर्ता था और उसके पीछे जगन्नाथ थे। अचानक आरोपी राम प्रसाद, सेवा राम और परमेश्वरी अपने हाथों में लाठी लेकर और आरोपी सुंदर लाल अपने हाथ में कांटा लेकर अचानक गन्ने के खेत से बाहर आये और श्रीमती को पीटना शुरू कर दिया। जिस पर गेंदा देवी ने फरियादी और जगन्नाथ ने मदद की गुहार लगाई। इसके बाद आरोपी राम प्रसाद और सेवा राम ने शिकायतकर्ता को लाठियों से पीटा। फरियादी एवं जगन्नाथ ग्राम कांगावन की ओर भाग गये तथा आरोपी पूर्व की ओर भाग गये। शिकायतकर्ता और जगन्नाथ ने श्रीमती को देखा। गेंदा देवी को देखा तो धान के खेत में उसकी मौत हो चुकी थी। आरोपियों ने श्रीमती की हत्या कर दी थी। गेंदा देवी मुकदमे की दुश्मनी के कारण। इसके बाद शिकायतकर्ता ने एच गांव चंदपुरा के निवासियों और गांव के 'चौकीदार', प्रधान और अन्य लोगों को सूचित किया, जो शिकायतकर्ता के साथ मौके पर आए थे। अंधेरा हो गया था और डर के कारण वह तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन

नहीं आया। और पूरी रात शव की देखभाल में बैठा रहा। अगली सुबह 23.8.1980 को शिकायतकर्ता ने बीसलपुर पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. (Ex.Ka. 3) दर्ज कराई। अपराध संख्या 247 धारा 302/323 आईपीसी के तहत पंजीकृत किया गया था। बीसलपुर थाने और एस.ओ. मामले की जांच का जिम्मा रामलखन सिंह को सौंपा गया. विवरण जी.डी. में दर्ज किया गया था, जिसकी एक प्रति Ex.Ka 4. आई.ओ. साथ में एस.आई.साहबदीन के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और श्रीमती गेंदा देवी. के शव की जांच रिपोर्ट तैयार की (Ex.Ka8) । गेंदा देवी. के शव को सील कर दिया गया और नमूना सील संरक्षित कर लिया गया, जो पूर्व है (Ex.Ka.11.). I.O. ने स्थल निरीक्षण किया और साइट-प्लान तैयार किया(Ex.Ka.5.O। श्रीमती गेंदा देवी के शव पोस्टमार्टम का संचालन डॉ. वी पी अग्रवाल, ने किया। शिकायतकर्ता शौकत अली, जिन्हें चोटें आई थीं, की भी पी.एच.सी. में जांच की गई। बीसलपुर। उनकी चोट की रिपोर्ट पूर्व है।(Ex.Ka.1). जांच पूरी होने के बाद, I.O. अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया।

आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उन पर आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए। और धारा 323 आईपीसी की धारा 34 सहपठित। आरोपों को पढ़ा गया और आरोपी व्यक्तियों को समझाया गया, जिन्होंने खुद को दोषी नहीं बताया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

अभियोजन संस्करण के समर्थन में शौकत अली, (पी.डब्लू.1), डॉ. सी.के. चतुर्वेदी (पीडब्लू2) जिन्होंने शौकत अली और जगन्नाथ (पी.डब्ल्यू.3) की चिकित्सा जांच की, डॉ. वी.पी. अग्रवाल, (पीडब्लू 4) जिन्होंने मृतक श्रीमती का पोस्टमार्टम किया। गेंदा देवी, ए.सी. पंचम एफ सिंह (पीडब्लू 5), कांस्टेबल रामपाल शर्मा, (पीडब्लू 6) और जांच करने वाले एसआई रामलखन सिंह (पीडब्लू 7) को पेश किया गया। आरोपियों से पूछताछ की गई जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि उन्हें दुश्मनी के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

6. शौकत अली मुखबिर (पीडब्लू1) और जगन्नाथ (पीडब्लू-3) ने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। ट्रायल कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों के बयान पर भरोसा करते हुए दोषसिद्धि दर्ज की और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई। उच्च न्यायालय के समक्ष रुख यह था कि मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्ट भेजने में अत्यधिक देरी हुई थी। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने सात चोटें देखीं और उनमें से तीन कटे हुए घाव थे और 3, 4, 5 और 7 चोटें फटे हुए घाव थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि जिन तीन आरोपियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की थी, वे लाठियाँ पकड़े हुए थे, जबकि कांथी सेवा राम के पास थी, जिसे बरी कर दिया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया है कि धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध नहीं बनाया गया था।

7. अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध बनता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

8. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही अभियोजन पक्ष के संस्करण को समग्र रूप से स्वीकार कर लिया जाए, फिर भी धारा 302 के तहत अपराध नहीं बनता है, धारा 34 आईपीसी के आवेदन से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है।

9. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

10. (जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था कि चश्मदीद गवाह पीडब्लू 1 और 3 के साक्ष्य में कोई खराबी नहीं थी।) इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना और दोषी ठहराना उचित था।

11. जहां तक यह प्रश्न है कि क्या अपीलकर्ताओं पर धारा 302 लागू की जाएगी, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 34 की पृष्ठभूमि में उनके मामलों पर विचार किया।

12. (धारा 34 किसी आपराधिक कृत्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियमित की गई है। धारा केवल साक्ष्य का नियम है और कोई ठोस अपराध नहीं बनाती है। धारा की विशिष्ट विशेषता कार्रवाई में

भागीदारी का तत्व है। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य के दौरान दूसरे द्वारा किए गए अपराध के लिए एक व्यक्ति का दायित्व धारा 34 के तहत उत्पन्न होता है यदि ऐसा आपराधिक कृत्य उन व्यक्तियों के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है जो अपराध करने में शामिल होते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामान्य इरादा शायद ही कभी उपलब्ध होता है और इसलिए, ऐसे इरादे का अनुमान केवल मामले के सिद्ध तथ्यों और ए सिद्ध परिस्थितियों से प्रकट होने वाली परिस्थितियों से लगाया जा सकता है। सामान्य इरादे के आरोप को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को स्थापित करना होगा साक्ष्य, चाहे प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, कि सभी आरोपी व्यक्तियों के मन में उस अपराध को करने की योजना या बैठक थी जिसके लिए उन पर धारा 34 की सहायता से आरोप लगाया गया है, चाहे वह पूर्व-व्यवस्थित हो या क्षणिक आवेग में; लेकिन यह भी आवश्यक रूप से अपराध के घटित होने से पहले होना चाहिए। धारा की वास्तविक अवधारणा यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति जानबूझकर संयुक्त रूप से कोई कार्य करते हैं, तो कानून में स्थिति बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि उनमें से प्रत्येक ने इसे व्यक्तिगत रूप से स्वयं किया हो। जैसा कि अशोक कुमार बनाम पंजाब राज्य [1977(1) SCC 746] में देखा गया की किसी अपराध में भाग लेने वालों के बीच एक सामान्य इरादे का अस्तित्व इस धारा के आवेदन के लिए आवश्यक तत्व

है। (यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपराध को संयुक्त रूप से करने का आरोप लगाए गए कई व्यक्तियों के कार्य समान या समान रूप से समान होने चाहिए। कार्य चरित्र में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एक ही सामान्य इरादे से क्रियान्वित किया जाना चाहिए प्रावधान को आकर्षित करें.)

13. (धारा "सभी के सामान्य इरादे" नहीं कहती है, न ही यह "सभी के लिए सामान्य इरादा" कहती है। धारा 34 के प्रावधानों के तहत दायित्व का सार एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में पाया जाना है आरोपी ऐसे इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य कर रहा है। धारा 34 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आवेदन के परिणामस्वरूप, जब किसी आरोपी को धारा 34 सहपठित धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाता है, तो कानून में इसका मतलब है कि आरोपी उत्तरदायी है उस कार्य के लिए जिसके कारण मृतक की मृत्यु उसी तरह से हुई जैसे कि यह उसके द्वारा अकेले किया गया था। प्रावधान का उद्देश्य ऐसे मामले को पूरा करना है जिसमें किसी पार्टी के अलग-अलग सदस्यों के कृत्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो सकता है जो आगे कार्य करते हैं सभी के सामान्य इरादे के बारे में या यह साबित करने के लिए कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या हिस्सा लिया था।) जैसा कि चिंता पुल्ला रेड्डी बनाम ए.पी. राज्य [1993 सप्लिमेंट] में देखा गया था। (3) एससीसी 134]। (धारा 34 तब भी लागू होती है जब

विशेष अभियुक्त द्वारा स्वयं कोई चोट न पहुंचाई गई हो। धारा 34 लागू करने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष कृत्य दिखाना आवश्यक नहीं है।

14. उपरोक्त स्थिति को गिरिजा शंकर बनाम यूपी राज्य [2004(3) SCC 793] मामले में उजागर किया गया था।

15. (जब तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर ऊपर प्रकाश डाले गए सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जाता है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह होता है कि अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 सहपठित 302 के संदर्भ में सही दोषी ठहराया गया है।)

12. अपील निराधार है और खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश कुमार-II (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।